[2009] 5 एस. सी. आर 1

राजस्थान राज्य

वी.

भानवर लाल और ए. एन. आर.

(2003 की आपराधिक अपील No.145)

3 मार्च, 2009

[डॉ. अरिजीत पासायत और अशोक कुमार गांगुली, जे. जे।]

मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धारा 50 के तहत राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अभियुक्त का अधिकार माना गया। धारा 50 में 'निकटतम' शब्द का उपयोग प्रासंगिक है – तलाशी जल्द से जल्द की जानी चाहिए और, एक बार व्यक्ति ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुना जाता है, यह पुलिस अधिकारी का काम है जिसे तलाशी लेनी है, सुविधाजनक रूप से उपलब्ध अधिकारी की उपस्थिति में इसे संचालित करना है – तथ्यों पर, गैर–अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने को दर्ज किया गया है धारा 50 उचित नहीं है।

धारा 27 – अफीम की जब्ती – जब्त की गई मात्रा ई 25 ग्राम से कम थी – माना गया: धारा 27 में शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या जी 0.327 ई दिनांक 16/7/1996 के संदर्भ में लागू है अधिनियम की धारा 27 के तहत – चूंकि आरोपी दो साल और 7 महीने से अधिक समय से हिरासत में है, इसलिए सजा पहले से ही बिताई गई अवधि तक सीमित है।

उत्तरदाताओं को नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के साथ पठित धारा 8 के तहत दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ और बरी करने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय के अपील में, राज्य–अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय सबूतों को खारिज करता रहा।

गवाही की तुलना में कथित भिन्नता के आधार पर पुलिस अधीक्षक पीडब्लू.16 पीडब्लू.12. यह इंगित किया गया कि पीडब्लू.16 में कहा गया है कि उसने आरोपी व्यक्तियों से पूछा कि क्या वे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेना चाहते हैं, इस अर्थ में कि वह स्वयं एक राजपत्रित अधिकारी थे। पीडब्लू.12 में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों से पूछा गया था कि क्या वे स्वयं पीडब्लू.16 या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहते हैं। अपीलकर्ता–राज्य के अनुसार यह साक्ष्य पढ़ने का उचित तरीका नहीं था।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जब्त की गई मात्रा 25 ग्राम से कम थी। उन्होंने अधिनियम की धारा 27 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या जी.ओ.327 ई दिनांक 16/7/1996 का हवाला दिया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 25 ग्राम तक अफीम के कब्जे में पाए जाने वाले आरोपी को ऐसी सजा दी जा सकती है। "थोड़ी मात्रा में" उनके मुताबिक 20 ग्राम की मात्रा उनके निजी इस्तेमाल के लिए थी

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

1.1. पीडब्लू 12 और 16 के साक्ष्यों को पढ़ने से राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच किए जाने के विकल्प का उपयोग करने के लिए अभियुक्त को दी गई जानकारी के संबंध में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं दिखा। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था। PW.16 का संस्करण Ext.P.8 में बताई गई बातों के अनुरूप था। [पैरा 5] [5–सी–डी]

राजस्थान राज्य बनाम राम चन्द्र 2005 (5) एससीसी 151, पर निर्भर।

1.2. जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा है, नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के तहत विकल्प केवल ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में खोला जाना है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का कोई और विकल्प नहीं है।

राजस्थान राज्य बनाम भंवर लाल और अन्य।

धारा 50 में प्रासंगिक है, तलाशी जल्द से जल्द की जानी चाहिए और, एक बार जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वह ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुनता है, तो यह पुलिस अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह किसकी उपस्थिति में तलाशी ले। सबसे आसानी से उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट है। बी इसलिए, दर्ज किया गया बरी करना उचित नहीं था। हालाँकि, प्रतिवादी ने सही तर्क दिया कि जब्त की गई मात्रा 25 ग्राम से कम थी। ऐसा होने पर, अधिनियम की धारा 27 ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के संदर्भ में लागू होती है। बताया गया है कि वह दो साल 7 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं. ऐसा होने पर सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक सीमित रखना उचित होगा। [पैरा 6 और 7] [6–एच; 7– ए]

केस कानून संदर्भ:

2005 (5) एससीसी 151 पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या145/2003

राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर के एस.बी. में दिनांक 07.02.2002 के निर्णय और आदेश से। आपराधिक अपील संख्या 445/1999.

अपीलकर्ता के लिए डॉ. मनीष सिंघवी, एएजी (राजस्थान), मिलिंद कुमार, संदीप बजाज और अरुणेश्वर गुप्ता (एनपी)।

डूंगर सिंह, वी.जे. प्रतिवादियों की ओर से फ्रांसिस और अनुपम मिश्रा।

का फैसला सुनाया गया

डॉ.अरिजीत पसायत, जे. 1. राजस्थान राज्य द्वारा इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दी गई है जिसमें भंवर लाल और मोहन लाल को बरी करने का निर्देश दिया गया है। इन दोनों उत्तरदाताओं आरोपी व्यक्तियों को कथित रूप से अपराध करने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में एनडीपीएस अधिनियम') की धारा 8 और 18 के तहत दंडनीय है। आरोपी मोहन लाल को धारा 18 के साथ पठित धारा 8 के संदर्भ में दोषी ठहराया गया और डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये) के जुर्माने के साथ दस साल की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता भंवर लाल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 18 के तहत दोषी ठहराया गया और 2,00,000/– रुपये (दो लाख रुपये) के जुर्माने के साथ 12 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित धारा 8 के तहत अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया था और इसलिए, डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 2,000/– रुपये के जुर्माने के साथ अलग से दो साल की सजा सुनाई गई थी।

2. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूत विश्वसनीय और ठोस हैं और जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोषसिद्धि दर्ज की गई। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया और बरी करने का निर्देश दिया।

3. विद्वान वकील द्वारा हमारे संज्ञान में यह लाया गया है कि आरोपी भंवर लाल की 12/10/2003 को मृत्यु हो गई है और इसलिए जहां तक उसका संबंध है, अपील खारिज की जाती है।

4. अभियुक्त मोहन लाल के मामले में, अपीलकर्ता राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय डिप्टी के साक्ष्य को खारिज कर दिया। गवाही की तुलना में कथित भिन्नता के आधार पर पुलिस अधीक्षक पीडब्लू.16 पीडब्लू.12. यह इंगित किया गया है कि जबकि PW.16 में कहा गया है कि उसने अभियुक्तों से पूछा कि क्या वे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेना चाहते हैं, इस अर्थ में कि वह स्वयं एक राजपत्रित अधिकारी था। पीडब्लू.12 में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों से पूछा गया था कि क्या वे स्वयं पीडब्लू.16 या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहते हैं। अपीलकर्ता–राज्य के विद्वान वकील के अनुसार साक्ष्यों को पढ़ने का उचित तरीका नहीं है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि जब्त की गई मात्रा 25 ग्राम से कम थी। उक्त संदर्भ अधिसूचना संख्या जी.ओ. 327 ई दिनांक 16/ का है।

राजस्थान राज्य बनाम भंवर लाल और अन्य।

[डॉ। अरिजीत पसायत, जे.]

केंद्र सरकार की धारा 7/1996 अधिनियम की धारा 27 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई है, जिसमें प्रावधान है कि यदि किसी आरोपी के पास 25 ग्राम तक अफीम पाई जाती है तो ऐसे आरोपी को "कम से कम" वाली सजा दी जा सकती है। उनके अनुसार, 20 ग्राम की मात्रा प्रतिवादी के निजी उपयोग के लिए थी। यह भी बताया गया है कि वसूली 23/12/1996 को की गई थी और इसे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भेजा गया था जहां कथित तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया था और इसे वापस पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था। प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार इस कार्रवाई के लिए क्या प्रेरित किया गया, यह अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

5. पीडब्लू 12 और 16 के साक्ष्यों को पढ़ने से राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच किए जाने के विकल्प का उपयोग करने के लिए अभियुक्त को दी गई जानकारी के संबंध में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं दिखता है। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था। PW.1'6 का संस्करण Ext.P.8 में बताई गई बातों के अनुरूप है।

6. इसे 2005 में पैरा 13 (5) एससीसी 151 में निम्नानुसार देखा गया था।

"धारा 50 में कोई आत्म–दोषारोपण शामिल नहीं है। यह केवल एक आरोपी (संदिग्ध) के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे किसी निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा आवश्यक होने पर तलाशी लेने के अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाता है। यहा यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि बाद के चरण में आरोपी (संदिग्ध) यह दलील न दे कि ये वस्तुएं उसके ऊपर लगाई गई थीं या ये वस्तुएं उसके पास से बरामद नहीं की गई थीं। इसे अलग तरीके से कहें तो, निष्पक्षता और पारदर्शिता खोज की प्रक्रिया को प्रधानता दी गई है। रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में धारा 50 का असली सार निम्नलिखित तरीके से उजागर किया गया था। (एससीसी पीपी.204–05, पैरा 8–11)

"8. जो प्रश्न हमें संदर्भित किया गया है उस पर मनोहर लाल बनाम राजस्थान राज्य में 22–1–1996 को दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने विचार किया था।

(वर्मा, जे.) ने बेंच की ओर से बोलते हुए कहा:

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 से यह स्पष्ट है कि आरोपी को दिया गया विकल्प केवल यह चुनना है कि क्या वह तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा या निकटतम उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या निकटतम उपलब्ध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट का चयन तलाशी लेने वाले अधिकारी को करना होता है, न कि आरोपी को।'

9. हम मनोहर लाल मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

10. किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तुएं पाए जाने पर जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध हैं, उसे यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि वह इसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहा था और यह उसे गंभीर दंड के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसलिए, यह अधिनियम तलाशी लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है।

11. अधिनियम की धारा 50 के तहत विकल्प, जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है, केवल ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का है। राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का कोई और विकल्प नहीं है। धारा 50 में 'निकटतम' शब्द का प्रयोग प्रासंगिक है। तलाशी यथाशीघ्र की जानी चाहिए और एक बार जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वह ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुनता है, तो यह पुलिस अधिकारी का काम है जिसे तलाशी लेनी है और जो भी व्यक्ति है उसकी उपस्थिति में तलाशी लेना है। सबसे आसानी से उपलब्ध, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट।"

7. इसलिए, दर्ज किया गया बरी होना उचित नहीं था। हालाँकि, जैसा कि विद्वान वकील ने सही तर्क दिया है

राजस्थान राज्य बनाम भंवर लाल और अन्य।

[डॉ। अरिजीत पसायत, जे.]

प्रतिवादी मोहन लाल ने कहा कि जब्त की गई मात्रा 25 ग्राम से कम थी। ऐसा होने पर, अधिनियम की धारा 27 ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के संदर्भ में लागू होती है। बताया गया है कि वह दो साल 7 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं, ऐसा होने पर सज़ा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक सीमित रखना उचित होगा। उपरोक्त बी को अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

Digitally signed by CHHANGUR RAM
Date: 2023.10.16 10:28:58 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court